

पेज नंबर 1/3
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 38/2011

अपीलांट

हरदेव पुत्र श्री मुलाराम के कायम मुकाम
1/1 इमरती बेवा हरदेवराम जाति मेघवाल निवासी बालुपुरा तहसील
जैतारण जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. मांगीलाल पुत्र मुलारामजी
2. रतनलाल पुत्र मुलारामजी
3. कालुराम पुत्र मुलाराम के कायम मुकाम—
3/1 राजुराम पुत्र स्वर्गीय कालुराम
3/2 बाबूलाल पुत्र स्वर्गीय कालुराम
3/3 कमली पत्नी स्वर्गीय कालुराम
4. भवरुराम पुत्र अनोपराम
5. हडमाल पुत्र अनोपराम
6. छोटुराम पुत्र अनोपराम
7. सावरिया पुत्र अनोपराम
8. नारायण पुत्र जोगाराम जातिगण मेघवाल निवासीगण बालुपुरा तहसील
जैतारण जिला पाली।
9. श्री आर. के व्यास महाप्रबंधक, वास्ते मैसर्स अंबुजा सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड
मुकाम राबडियावास, तहसील जैतारण जिला पाली।
10. तहसीलदार व उपपंजीयक अधिकारी जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

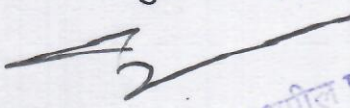
उपस्थित :-

1. श्री शरीफ काजी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री मनीष राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 से 3/3
3. शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।
4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 10 की ओर से

—: निर्णय :-

दिनांक : 20.05.2019.

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 34/2010 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.11.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब


राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पेज नंबर 2/3

किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया। रेस्पॉडेन्ट संख्या 04 से 09 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उक्त पक्षकारान के विरुद्ध गुणवागुण पर निर्णय पारित किया जाता है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पॉडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा बालूपूरा के खसरा नंबर 16/1, 24, 29, 84 रकबा 122 बीघा 06 बिस्वा के संबंध में प्रस्तुत कर 1/4 हिस्सा घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी का रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार है। जिस पर अपीलान्ट 40 वर्षों से काश्त कर रहा है। वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा दर्ज है व अनोपराम का भी 1/2 हिस्सा दर्ज है। उपरोक्त हिस्से का 18 रुपये का बंटवारानामा 14.01.1971 के द्वारा किया गया व म्यूटेशन संख्या 42 अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 06.06.1972 में भरा गया। उक्त म्यूटेशन के विरुद्ध रेस्पॉडेन्ट संख्या 01 से 03 द्वारा आदिनांक तक कोई वाद सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। रिको द्वारा दिनांक 14.10.1994 को भूमि अवाप्त की जाकर अंबुजा सीमेंट के नाम म्यूटेशन अमल दरामद किया गया, उक्त कार्यवाही में रेस्पॉडेन्ट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नहीं की गई। जिससे यह स्पष्ट है कि रेस्पॉडेन्ट का वादग्रस्त आराजी पर कोई हक अधिकार नहीं है। रेस्पॉडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद को कैम्प में निर्णीत किया गया है जबकि राजस्व न्यायालय को कन्टेस्टेड प्रकरण में राजीनामा करवाने का कोई अधिकार नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को धोखे में रखकर बिना वाद की जानकारी दिये कम्प्यूटर से टाईपशुदा राजीनामे की प्रति पर हस्ताक्षर करवाये गये, जो राजीनामा कतई तस्दीक नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये, तनकीयात कायम किये, राजस्व कैम्प कोर्ट में जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अत अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाई जावे।

वकील रेस्पॉडेन्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पॉडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा बालूपूरा के खसरा नंबर 16/1, 24, 29, 84 रकबा 122 बीघा 06 बिस्वा के संबंध में प्रस्तुत कर 1/4 हिस्सा घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट एवं रेस्पॉडेन्टगण की पुश्तैनी आराजी है। जिस पर रेस्पॉडेन्ट का जन्म से हक अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पॉडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत वाद में लोक अदालत मजमा-ए-आम ग्राम राबडियावास में आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान 2010 शिविर में दिनांक 25.11.2010 को उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तस्दीक शुदा राजीनामों के आधार पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 की अनुसूची प्रथम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

3
राजस्थान अपील प्राधिकारी
पाली

पेज नंबर 3/3

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा बालूपूरा के खसरा नंबर 16/1, 24, 29, 84 रकबा 122 बीघा 06 बिस्वा के संबंध में प्रस्तुत कर 1/4 हिस्सा घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवाद सत्य है कि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी आराजी है। जिस पर अपीलांत का वक्त जन्म से हक हिस्सा है। एवं जहां तक वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 के कब्जे का प्रश्न है तो पुश्तैनी आराजी पर कब्जे का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत वाद में अपीलांत एवं रेस्पोंडेन्ट द्वारा लोक अदालत मजमा-ए-आम ग्राम राबडियावास में आयोजित प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 शिविर में दिनांक 25.11.2010 को तस्दीक शुदा राजीनामा प्रस्तुत किया। उक्त राजीनामे में वर्णित तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 की अनुसूची प्रथम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामों में वर्णित तथ्यों के आधार जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। जिसमें हमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 34/2010 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.11.2010 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड लौटाया जावे। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 20.05.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली